विभाग का नाम :- रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसायिटी
विभाग का पता:- पुराना कोर्ट बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या:- 5
दिनांक:- 15.12.2023
प्रश्नकर्त्ता का नाम:- श्री शरद चौहान
क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) वर्तमान में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक कितने घाटे में है, बताया जाए;	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2022–2023 के अनुसार बैंक को इस वित्तीय वर्ष में 94,97,598.40 रूपए का घाटा हुआ है। बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार अर्धवार्षिक अनऑडिट रिपोर्ट 2023–24 में रूपया 147.03 लाख लाभ दर्शाया गया है।
(ख) वर्तमान निदेशक श्री अतुल भारद्वाज क्या पूर्व में बैंक के कर्मचारी थे, यदि हां, तो उनकी सर्विस की सम्पूर्ण फाइल की कॉपी दें;	जी हां। बैंक द्वारा दी जानकारी के अनुसार श्री अतुल भारद्वाज की सेवा फाइल इस दलील पर देने से इनकार कर दिया है कि उनके रोजगार का सेवा रिकार्ड विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी है, जिसका व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है और ऐसी सूचना को देने से बैंक पर अदालती कार्यवाही हो सकती है। इस विषय में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को इस विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि मांगी गई जानकारी सात दिनों के अंदर भेजी जाए अन्यथा डीसीएस एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। जैसे ही बैंक से जानकारी प्राप्त होगी माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
(ग) कर्मचारी श्री सार्थक गुप्ता के खिलाफ कितने जांचे चल रही हैं, सभी का ब्यौरा दें;	बैंक द्वारा दी जानकारी के अनुसार श्री सार्थक गुप्ता के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) के तहत अनिल कुमार गौड़ बनाम दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य शीर्षक से रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की अदालत में मामला लंबित है।

(घ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के सभी कोर्ट में जैसे आरसीएस, डीसीटी, एफसी, जिला न्यायालय एवं हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं सभी में विभाग का क्या स्टैंड हैं और उनमें वकील कौन–कौन हैं;	विभाग नियमानुसार विषय की योग्यता एवं गुणवत्ता के आधार पर स्टैंड लेता है। केस अनुसार संक्षिप्त विवरण तथा वकीलों की सूची (अनुलग्नक ए, बी, सी, डी) संलग्न है। विभाग द्वारा ऐसे मामलों में जिस आधार पर स्टैंड लिया जाता है वह भी संलग्न है। (अनुलग्नक ई)
(ड.) क्या वर्तमान निदेशक श्री अजीत सिंह व उनके पुत्र श्री सुधीर पर एफआईआर दर्ज है, तो विभाग ने उन्हें अभी तक हटाया क्यों नहीं; और	बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्तमान निदेशकों में से एक श्री अजीत सिंह और उनके बेटे श्री सुधीर कुमार के खिलाफ एफआईआर संख्या 129/2018यू/एस/406/468/420/120–बी आईपीसी के तहत ईओडब्ल्यू सेल के समक्ष एक एफ़आईआर लंबित है, जिसकी आज तक जांच लंबित है। प्राथमिकी में उल्लिखित ऋण खाते 21.11.2016 को ही समाप्त हो चुके हैं, जो कि उनके पिछले बोर्ड में निदेशक बनने से पहले ही है। डीसीएस अधिनियम और नियमों में किसी निर्वाचित निदेशक को प्राथमिकी के आधार पर हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। सीईओ, डीएनएसबी को इस कार्यालय ने द्वारा सेवा नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने एवं इस कार्यालय को अवगत करने का निर्देश दिया गया है जैसे ही बैंक से जानकारी प्राप्त होगी माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
(च) विगत पांच वर्षो में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के कर्मचारियों की प्रमोशन को लेकर कितनी बार आरसीएस अधिकारियों की कमेटी बनाई गई और कमेटी की रिपोर्ट क्या है, यदि अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं दी है तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाही हो सकती है?	विभाग में उपलब्ध अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक 03.12.2019 को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए आरसीएस द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने एक अंतरिम रिपोर्ट आरसीएस के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिस पर आरसीएस ने कमेटी को विस्तृत जांच करने के लिए आदेश किया था। तथापि इसके उपरांत वैश्विक महामारी कोरोना का भारत में आगमन हो गया था।

	कोरोना महामारी के आगमन के कारण सभी अधिकारी कोरोना ड्यूटी पर लगा दिया गये थे एवं कमेटी के दो सदस्यों का कोरोना महामारी के दौरान ही स्थानांतरण अन्य विभागों में हो गया था। इस कार्यालय ने नई समिति का गठन कर 2 माह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जैसे ही कमीटी से रिपोर्ट प्राप्त होगी माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी

A. K. SINGH, IAS
Registrar Co-operative Societies
Govt. of N.C.T. of Delhi
Parliament Street, New Delhi-110001

अनुलग्नक ए

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से संबंधित उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं	मामला संख्या	शीर्षक	सरकारी वकील का विवरण (नाम)	मामले का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1	रिट याचिका सिविल नंबर 12346/2019	रमन कौशिक बनाम आरसीएस और अन्य।	जवाहर राजा (एएससी)	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में नियुक्त अवैध कर्मचारी की बर्खास्तगी के संबंध में	जवाबी हलफनामा और अपेक्षित दस्तावेज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है।
2	रिट याचिका सिविल नंबर 1710/2022	सुधा शर्मा बनाम दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	संतोष कुमार त्रिपाठी (एससी)	याचिकाकर्ता दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से बकाया वेतन आदि की मांग कर रहा है।	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05/04/2023 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 (आरसीएस) की ओर से कोई प्रति शपथ पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं है।
3	रिट याचिका सिविल नंबर 7921/2016	अनिल कुमार गौड़ बनाम भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य।	अवनि सिंह (वकील)	आरबीआई ऋण फाइलों का निरीक्षण करेगा, जो वर्तमान में श्री नवीन कटारिया की हिरासत में है। (डीआरसीएस, आरटीडी.)।	जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया गया है और आरसीएस को कोई और निर्देश नहीं दिया गया है
4	रिट याचिका सिविल	कृष्ण कुमार मित्तल बनाम	जवाहर राजा (एएससी)	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक द्वारा दोषी कर्मचारी	जवाबी हलफनामा प्रस्तुत कर दिया गया है

अनुलग्नक 'ए'

	नंबर 14090/2021	आरसीएस और अन्य।		श्री पदम डबास का निलंबन	और आरसीएस परफॉर्मा पार्टी है।
5	रिट याचिका सिविल नंबर 15695/2022	दिनेश कुमार शर्मा बनाम आरसीएस और अन्य।	समीर वशिष्ठ (एएससी)	सेरियोरारी की रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिससे दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 के तहत विद्वान दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 04.10.2022 के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाए।	चुनाव का मामला (आरसीएस इस मामले में परफॉर्मा पार्टी है।
6	रिट याचिका सिविल नंबर 7007/2023	श्रीमती सुमित्रा देवी और अन्य वनाम आरसीएस और अन्य।	श्री उदित मलिक (एएससी)	परमादेश की रिट या उसकी प्रकृति में कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिससे प्रतिवादी नंबर 2 यानी रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी को संपत्ति के शीर्षक दस्तावेजों को जारी करने का निर्देश दिया जा सके। (ऋण का मामला)	जवाबी हलफनामा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है।

अनुलग्नक 'ए'

7.	रिट याचिका सिविल नंबर 16227/2022	डीएनएसबी बनाम आरसीएस एवं अन्य।	श्री अनुपम श्रीवास्तव (एएससी)	एफ.नं.एआर/वीकेजी/सीडी नंबर 107525772 वाली कार्यवाही में आरसीएस, दिल्ली-प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 को रद्द करने/अलग करने के लिए सर्टिओरारी रिट की प्रकृति में एक रिट या निर्देश जारी करने के लिए /आरसीएस/2018/748-750 जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई और डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 115 के तहत समीक्षा आवेदन और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अधिनियम की धारा 117 के तहत आवेदन को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खारिज कर दिया गया; ऐसे अन्य और अतिरिक्त आदेश पारित करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उचित समझे जाएं।	आरसीएस इस मामले में प्रतिवादी नंबर 1 है और आरसीएस पर कोई अनुपालन लंबित नहीं है।

अनुलग्नक 'बी'

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से संबंधित वित्तीय आयुक्त में लंबित अदालती मामलों का विवरण				
क्रमांक	मामला संख्या	शीर्षक	सरकारी वकील का विवरण(नाम)	मामले का संक्षिप्त विवरण
1	237/2017	श्री कृष्ण कुमार मित्तल बनाम आरसीएस एवं अन्य।	वासु सिंह	याचिकाकर्ता ने डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण शुरू करने के लिए आरसीएस कार्यालय द्वारा जारी अधिकारी आदेश संख्या एआर/बीकेजी/आरसीएस/2017/374-80 दिनांक 29.08.2017 को रद्द करने और श्री पी.सी. जैन (जांच अधिकारी) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पीए/एसडी/डब्ल्यूसीडी/जाँच अधिकारी/2017/18157-81 दिनांक 04.09.2017 को रद्द करने का अनुरोध किया है।
2	190/2019	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आरसीएस	वासु सिंह	आवेदक ने आदेश संख्या एआर/बीकेजी/आरसीएस/2018-982 दिनांक 14.02.2019 को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत आरसीएस ने बैंक में नए सदस्य का नामांकन बंद कर दिया था ।
3	191/2019	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आरसीएस	वासु सिंह	आवेदक ने आदेश संख्या एआर/बीकेजी/आरसीएस/2018-982 दिनांक 14.02.2019 को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत आरसीएस ने बैंक में नए सदस्य का नामांकन बंद कर दिया था ।
4	211/2023	संगीता बनाम दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	वासु सिंह	यह एक नया मामला है और आरसीएस इस मामले में केवल परफॉर्मा पार्टी है।
5	204/2017	जय भगवान बनाम आरसीएस	वासु सिंह	याचिकाकर्ता ने दिनांकित 20.04.2016 निरीक्षण आदेश जो डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति के लिए जारी किया गया था को रद्द करने का अनुरोध किया है।

Am

अनुलग्नक 'बी'

6	427/2018	श्री कृष्ण कुमार मित्तल बनाम आरसीएस एवं अन्य।	वासु सिंह	याचिकाकर्ता ने फाइल संख्या एफ.नं. वाली रिपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध किया है। डीआरसीएस/बीकेजी/2018/78 दिनांक 31.05.2018 और डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 66 (2) के संबंध में कारण बताओ नोटिस संख्या आरसीएस/बीकेजी/2018/66(2)/5357-5378 दिनांक 04.10.2018।
7	33/2020	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आरसीएस एवं अन्य।	वासु सिंह	याचिकाकर्ता ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के विशेष ऑडिट के संचालन के लिए आरसीएस द्वारा जारी डीसीएस नियम 2007 की धारा 80 के तहत जारी आदेश संख्या 107582457/आरसीएस/2019/76-77 दिनांक 28.11.2019 को रद्द करने का अनुरोध किया है।
8	168/2023	विनय भारद्वाज बनाम आरसीएस	बिंदिया सांवरा	याचिकाकर्ता ने निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति के लिए आरसीएस द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.सं.एआर/बीकेजी/आरसीएस/61/2023/5351-5355 दिनांक 04.07.2023 को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अनुलग्नक 'सी'

'1'

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के जिला न्यायालय में लंबित अदालती मामलों का विवरण

क्रमांक	मामला संख्या	शीर्षक	सरकारी वकील का विवरण(नाम)	न्यायालय का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण
1	2395/2019	आरसीएस बनाम राजेश शर्मा और अन्य। थाना करावल नगर	अंकित गुप्ता	कड़कड़डूमा कोर्ट	आरसीएस ने डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 118 और धारा 403, 405, 406, 408, 409 एवं आईपीसी की धारा 415, 418, 420, 465, 468, 471, 477ए 120, 120 बी आर/डब्ल्यू 34 के तहत दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की करावल नगर शाखा के सदस्यों के नामांकन में अनियमितता में शामिल व्यक्तियों को तलब करने के लिए माननीय कड़कड़डूमा अदालत का रुख किया है।
2	13326/2019	आरसीएस बनाम श्री जीतेन्द्र गुप्ता	वासु सिंह	एमएम कोर्ट तीस हजारी	रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 118 (1) और बी (6) और धारा 403 के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 और दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 की धारा 121 के तहत शिकायत दर्ज की है। , आईपीसी की धारा 405, 406, 408, 409, 415, 420, 465, 468, 471, 477ए के तहत माननीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष श्री अनिल कुमार गौड़ से प्राप्त शिकायत दिनांक 24.05.2016 के आधार पर दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में कदाचार का आरोप लगाया गया था।

अनुलग्नक 'डी'

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में आरसीएस की अदालत में लंबित मामलों का विवरण।

क्रम संख्या	शीर्षक	मामले
1.	सदन सिंह यादव बनाम दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	एससीएन दिनांक 04.10.2018 के माध्यम से डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) के तहत कार्यवाही।
2.	अनिल गौड़ वी.एस. दिल्ली नागरिक बैंक लिमिटेड के पूर्व निदेशक मंडल	एससीएन दिनांक 19.06.2018 के तहत डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) के तहत दिवाली उपहारों के लिए धन के दुरुपयोग की कार्यवाही।
3.	श्री अनिल गौड़ बनाम सार्थक गुप्ता एवं अन्य	एससीएन दिनांक 08.11.2019 के माध्यम से डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) के तहत कार्यवाही।

आनुलग्नक 'ई'

Stand of the Department

1	Registrar Cooperative Societies contest court cases as per the provision of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 and Rules framed thereunder.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अदालती मामले लड़ती हैं।